Brooks
LABORATORIES LIMITED

Corp. Off.:- 201, "The Summit Business Bay"
Behind Guru Nanak Petrol Pump,
Off Andheri Kurla Road, Andheri (E),
Mumbai - 400 093 (India)
Ph. : +91 22 69073100

14th August 2026

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai-400001

Scrip Code: **533543**

National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, C-1, Block G
Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai-400051

Symbol: **BROOKS**

Subject: Intimation pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed extracts of the newspaper publications published in Financial Express (all edition) and Jansatta, (Chandigarh edition) on 14th August 2026, relating to the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended 30th June 2026.

Enclosed herewith copy of the newspapers cuttings.

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours faithfully
For **BROOKS LABORATORIES LIMITED**

RANE KRUTIKA MOHAN
Digitally signed by RANE KRUTIKA MOHAN
Date: 2026.08.14 17:24:59 +05'30'

Krutika Rane
Company Secretary and Compliance Officer
Membership no. 66310
Encl.: As Above

एड्स के मामलों में 175 फीसद की बढ़ोतरी

प्रदेश में 2021-22 में 363 से बढ़कर 2024-25 में 1,000 हुए मरीज

शिमला, 13 अगस्त (जनसत्ता)।

प्रदेश में एचआइवी संक्रमण से जुड़े आंकड़ों में बीते कुछ वर्षों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एकीकृत एसटीआइ, एचआइवी, टीबी और हेपेटाइटिस बी-सी परीक्षण एवं उपचार अभियान के आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में सामने आए 363 नए एचआइवी मामले वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1,000 हो गए। इस तरह तीन वर्षों में नए मामलों में करीब 175 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2025-26 में सामने आए मामलों के विश्लेषण में 19 फीसद संक्रमण सिरिंज साझा करने से जुड़ा पाया गया।

पीटरहाफ शिमला में अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश में एचआइवी संक्रमण की रोकथाम, जांच, उपचार और जागरूकता से जुड़े आंकड़े सामने रखे गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल ने की। प्रदेश में एचआइवी को लेकर जागरूकता अभियान को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए आशा कार्यकर्ताओं की मदद ली जा रही है।

करीब 1,000 आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से पांच जिलों के 2,440 गांवों में 2.86 लाख परिवारों तक एचआइवी से बचाव, जांच और उपचार से संबंधित संदेश पहुंचाया गया है। विधायक हरीश जनारथा ने कहा कि एचआइवी के खिलाफ लड़ाई केवल वायरस के खिलाफ नहीं, बल्कि अज्ञानता, डर, गलत धारणाओं, कलंक और भेदभाव के खिलाफ भी है। कार्यक्रम में बताया गया कि यूएनएड्स के 95-95-95 लक्ष्य को हासिल करने में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। इस लक्ष्य के तहत एचआइवी से संक्रमित लोगों की पहचान करने, उन्हें उपचार से जोड़ने व उपचार के बाद संक्रमण को नियंत्रित रखने पर जोर दिया जाता है।

शिमला में अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश में एचआइवी संक्रमण की रोकथाम, जांच, उपचार और जागरूकता से जुड़े आंकड़े सामने रखे गए।

सिरिंज साझा करने से 19 फीसद संक्रमण

वर्ष 2025-26 में सामने आए एचआइवी मामलों के कारणों के विश्लेषण में 19 फीसद संक्रमण सिरिंज साझा करने से संबंधित पाया गया। यह आंकड़ा नशीली दवाओं के सेवन के दौरान सिरिंज साझा करने से संक्रमण फैलने के जोखिम को सामने लाता है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच और जागरूकता गतिविधियों को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।

तीन जिले सुरक्षित श्रेणी में

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश में एड्स से सुरक्षित माने जाने वाले 15 जिलों में हिमाचल के किन्नौर, लाहौल-स्पीति और सोलन शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश के तीन अन्य जिले भी सक्षम श्रेणी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि एचआइवी संक्रमण के लिए जांच, उपचार और जागरूकता अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं।

रैली

शिमला में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आयोजित तिरंगा यात्रा में भाग लेते स्कूली विद्यार्थी।

'सिकरीधार सीमेंट संयंत्र चंबा के लिए महत्त्वपूर्ण'

भाजपा सांसद राजीव भारद्वाज ने संसद में उठाया मुद्दा

शिमला, 13 अगस्त (जनसत्ता)।

चंबा के चुराह क्षेत्र में प्रस्तावित सिकरीधार सीमेंट संयंत्र का मामला लगभग डेढ़ दशक बाद एक बार फिर चर्चा में आया है। भाजपा सांसद राजीव भारद्वाज ने संसद में इस परियोजना का मुद्दा उठाते हुए इसे धरातल पर उतारने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

राजीव भारद्वाज

उनका कहना है कि इस सीमेंट संयंत्र के शुरू होने से न केवल चंबा, बल्कि पड़ोसी कांगड़ा जिले के युवाओं के लिए भी रोजगार के हजारों अवसर सृजित हो सकते हैं। ऐसे में लंबे समय से कागजों तक सीमित इस परियोजना को अब व्यावहारिक बाधाओं से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है। सिकरीधार सीमेंट परियोजना की परिकल्पना लगभग डेढ़ दशक पूर्व की गई थी। इस परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई थी, किंतु निवेशक कंपनी के आगे न आने के कारण यह आगे नहीं बढ़ सकी।

परियोजना के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा कमजोर सड़क संपर्क और क्षेत्र में आवश्यक आधारभूत ढांचे की कमी रही है। इसी कारण निवेश की संभावनाओं के बावजूद यह परियोजना अब तक धरातल पर साकार नहीं हो पाई है। सिकरीधार जैसे दुर्गम क्षेत्र में बड़े औद्योगिक संयंत्र की स्थापना के लिए मजबूत सड़क नेटवर्क एक अनिवार्य शर्त है। भारी मशीनरी और कच्चे माल के परिवहन के लिए सुगम संपर्क मार्ग के अभाव में सीमेंट उद्योग की लागत में वृद्धि होना स्वाभाविक है। ऐसे में सरकार को केवल परियोजना की स्वीकृति या निविदा प्रक्रिया तक सीमित न रहकर सड़क, बिजली, पानी तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास पर समानांतर रूप से कार्य करना होगा।

रोजगार सृजन के साथ अर्थव्यवस्था को मिल सकती है गति

चंबा आकांक्षी जिलों में शामिल है, जहां औद्योगिक रोजगार के अवसर सीमित हैं। इस परियोजना के क्रियान्वयन से संयंत्र में प्रत्यक्ष रोजगार के साथ-साथ परिवहन, निर्माण, होटल-ढाबा, छोटे व्यवसायों और स्थानीय सेवाओं के क्षेत्र में भी अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। इसका लाभ चंबा के साथ-साथ कांगड़ा जिले के युवाओं को भी प्राप्त हो सकता है। सांसद भारद्वाज ने इस परियोजना को चंबा-कांगड़ा क्षेत्र के लिए संभावित 'गेमचेंजर' बताते हुए केंद्र और राज्य सरकार से समन्वय स्थापित कर इसकी व्यावहारिक बाधाओं को शीघ्र दूर करने की अपील की है। अब यह देखना महत्त्वपूर्ण होगा कि डेढ़ दशक से लंबित यह परियोजना कब वास्तविक रूप से धरातल पर उतर पाती है।

हाई कोर्ट का 49 साल पुराने विवाद में फैसला

जमीन की देखरेख करने वाला मालिक नहीं बन सकता

शिमला, 13 अगस्त (जनसत्ता)।

हाई कोर्ट ने जमीन और काश्तकारी अधिकार से जुड़े करीब 49 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि किसी संपत्ति की लंबे समय तक देखरेख करने वाला या नौकर केवल इस आधार पर उस संपत्ति का मालिक या किराएदार होने का दावा नहीं कर सकता। न्यायाधीश रोमेश वर्मा ने प्रतिवादी की अपील खारिज करते हुए निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखा और वादी को उसकी संपत्ति का कब्जा दिलाने के निर्देश दिए।

मामला वर्ष 1977 में धर्मशाला की अदालत से शुरू हुआ था। वादी ने जमीन और मकान का कब्जा वापस लेने के लिए मुकदमा दायर किया था। उसका कहना था कि उसके पिता ने प्रतिवादी को अपनी अनुपस्थिति में केवल संपत्ति की देखरेख के लिए रखा था। आरोप था कि प्रतिवादी ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर खसरा गिरदावरी में खुद को किराएदार दर्ज करवा लिया।

हाई कोर्ट ने पाया कि वर्ष 1976 में प्रतिवादी का नाम किराएदार के रूप में दर्ज करते समय हिमाचल प्रदेश 'लैंड रिकार्ड्स मैनुअल' के नियम 9.8 और 8.15 का पालन नहीं किया गया। जीवित किराएदारी दर्ज करने से पहले तहसीलदार को दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देना जरूरी था। अदालत ने कहा कि मालिक की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर बिना निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के राजस्व रिकार्ड में किया गया बदलाव वैध अधिकार पैदा नहीं कर सकता। हाई कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि वादी करीब 49 वर्षों से अपनी ही संपत्ति के लिए न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है।

खबर कोना

अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, एक की मौत

कुल्लू, 13 अगस्त (जनसत्ता)।

कुल्लू में चयोगी के पास चढ़ाई पर फंसी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए धक्का दे रही पत्नी के सामने ही वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा, जिससे उसके पति की मौत हो गई। पुलिस जानकारी के अनुसार, मढ़ी (नगर) निवासी नरेंद्र कुमार परिवार के साथ घर लौट रहे थे। चयोगी के चढ़ाई पर गाड़ी बंद हो गई और वाहन को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र की पत्नी गाड़ी से नीचे उतरीं और पीछे से धक्का लगाने लगीं। इसी दौरान अचानक गाड़ी चालक नरेंद्र कुमार के नियंत्रण से बाहर हो गई और उसकी मौत हो गई।

मशरूम खाने से एक ही परिवार के आठ लोग बीमार

कुल्लू, 13 अगस्त (जनसत्ता)।

कुल्लू की लगघाटी के दुर्गम क्षेत्र दोघरी गांव में जंगली मशरूम खाने से एक ही परिवार के आठ लोग खाद्य विषाक्तता (फूड पाइजनिंग) का शिकार हो गए। सभी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू लाया गया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार प्रभावित लोगों की पहचान डोले राम (66), मोहन लाल (28), सुरेंद्र (26), सविता (25), भगवन्तु (24), नीलम (24), माहिरा (1 वर्ष) और जानवी (1 वर्ष) के रूप में हुई है। इनमें एक-एक वर्ष की मासूम बच्चियों माहिरा और जानवी को इंदिरा गांधी चिकित्सा कालेज व अस्पताल शिमला भेजा गया है।

संजौली-ढली मार्ग का एक सितंबर से होगा परीक्षण

शिमला, 13 अगस्त (जनसत्ता)।

चमियाना स्थित सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल जाने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने जा रही है। हाई कोर्ट ने संजौली चौक से ढली-चमियाना मार्ग को एक सितंबर से परीक्षण आधार पर छोटे वाहनों के लिए खोलने के आदेश जारी किए हैं। अदालत ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिमला को सुबह के समय सीमित यातायात बहाल करने के निर्देश दिए हैं।

शिमला में पानी फिर होगा महंगा, अगले साल आठ फीसद बढ़ेंगे दाम

शिमला, 13 अगस्त (जनसत्ता)।

राजधानी शिमला के लाखों निवासियों को आने वाले महीनों में पानी के लिए अधिक भुगतान करना होगा। पेयजल कंपनी ने अगले वर्ष मार्च से पानी की दरों में आठ फीसद वृद्धि करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष मार्च में भी पानी की दरों में आठ फीसद की बढ़ोतरी की गई थी। ऐसे में लगातार दूसरी बार होने वाली इस वृद्धि से शहरवासियों पर आर्थिक दबाव और बढ़ेगा।

प्रदेश सचिवालय में गुरुवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई पेयजल कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में दर वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार शिमला की 24 घंटे पेयजल आपूर्ति योजना के लिए विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता की शर्तों के तहत प्रत्येक वर्ष पानी की दरों में वृद्धि करना अनिवार्य है। इसी प्रावधान के तहत आठ फीसद वृद्धि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। बैठक के दौरान नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान और उपमहापौर उमा कौशल ने प्रस्तावित दर वृद्धि का विरोध किया।

उन्होंने कहा कि पहले से ही महंगाई का सामना कर रहे नागरिकों पर पानी की कीमतों में वृद्धि का अतिरिक्त भार नहीं डाला जाना चाहिए। हालांकि, विश्व बैंक की शर्तों का हवाला देते हुए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई। कंपनी के अनुसार वर्तमान में उपभोक्ताओं को पुराने दरों पर ही बिल जारी किए जाएंगे। नई दरें अगले वर्ष मार्च से प्रभावी होंगी।

विश्व बैंक की शर्त के चलते शहरवासियों पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ। प्रदेश सचिवालय में गुरुवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई पेयजल कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में दर वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अधिकारियों के अनुसार, विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता की शर्तों के तहत प्रत्येक वर्ष पानी की दरों में वृद्धि करना अनिवार्य।

प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार स्थगित

विधानसभा के मानसून सत्र के बाद होने की संभावना

शिमला, 13 अगस्त (जनसत्ता)।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के मंत्रिमंडल के बहुप्रतीक्षित विस्तार को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अब इसके विधानसभा के मानसून सत्र के बाद होने की संभावना जताई जा रही है। विस्तार टलने से मंत्री पद के प्रमुख दावेदार माने जा रहे कुल्लू सदर के विधायक सुंदर ठाकुर की प्रतीक्षा और बढ़ गई है। लंबे समय से मंत्रिमंडल में रिक्त एक पद को भरने को लेकर कांग्रेस के भीतर लगातार चर्चा जारी है।

मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर बुधवार को नई दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान और प्रदेश के शीर्ष नेताओं के बीच महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार उपस्थित रहे। सूत्रों के अनुसार बैठक में प्रदेश की राजनीतिक स्थिति, संगठन से जुड़े विषयों तथा मंत्रिमंडल विस्तार पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

पार्टी सूत्रों के अनुसार बैठक में संभावित नामों और राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा हुई, हालांकि तत्काल विस्तार को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। ऐसे में अब संकेत हैं कि विधानसभा के मानसून सत्र के बाद ही इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। सत्र के दौरान सरकार के समक्ष कई महत्त्वपूर्ण राजनीतिक एवं प्रशासनिक मुद्दे रहेंगे। इसके पश्चात आलाकमान के साथ पुनः चर्चा कर मंत्रिमंडल विस्तार को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। मंत्रिमंडल में रिक्त पद को लेकर कांग्रेस के कई विधायकों की नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि सुंदर ठाकुर को इस दौड़ में लंबे समय से एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है। संगठन और सरकार में उनकी सक्रिय भूमिका तथा कुल्लू क्षेत्र के राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए उनके नाम पर लगातार चर्चा होती रही है। विस्तार टलने से उनकी दावेदारी पर निर्णय भी फिलहाल कुछ समय के लिए आगे बढ़ गया है।

कांग्रेस महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के 18 अगस्त को शिमला आगमन की संभावना है। उनके प्रस्तावित दौरे को प्रदेश कांग्रेस के भीतर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व की नजर अब मानसून सत्र और उसके बाद विकसित होने वाले राजनीतिक घटनाक्रम पर है। माना जा रहा है कि सत्र समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू दिल्ली में आलाकमान के साथ पुनः बैठक कर सकते हैं, जिसके दौरान मंत्रिमंडल विस्तार पर अंतिम सहमति बनने की संभावना है।

मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर बुधवार को नई दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान और प्रदेश के शीर्ष नेताओं के बीच महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। *पार्टी* सूत्रों के अनुसार बैठक में संभावित नामों और राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा हुई, हालांकि तत्काल विस्तार को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका।